# गन्ना किसानों एवं जीडीए द्वारा पीड़ित किसानों की समस्याओं के हल हेतु आन्दोलन

गोरखपुर, 22 फरवरी, 2014। गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी एवं गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ जी महाराज महानगर ही नहीं, आसपास के ग्रामीण किसानों तथा जनपद व पूर्वी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भी अपनी आवाज बुलन्द करते रहे हैं। 22 फरवरी 2014 को जीडीए द्वारा पीड़ित किसानों की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय पर आयोजित धरना कार्यक्रम में भी वे सम्मिलित हुए एवं प्रशासन से समस्याओं के समाधान पर बल दिया। यह चेतावनी भी दी कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण से पीड़ित किसानों तथा गन्ना किसानों की समस्या का समाधान अविलम्ब हो। विकास के नाम पर चल रही लूटखसोट का शिकार अगर किसानों को बनाया गया तो इसका मुॅहतोड़ जवाब दिया जायेगा। धरने पर मानबेला, मिर्जापुर, झुंगिया, जंगल तिनकोनिया, खोराबार आदि क्षेत्र के किसान उपस्थित रहे।

योगी जी ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान विरोधी है, अब इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिये। 15 फरवरी को मानबेला में समाजवादी पार्टी की रैली में मौजूद प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर विकास प्राधिकरण से पीड़ित किसानों की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में न तो कुछ कहा गया और न ही उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान से सम्बन्धित वक्तव्य ही दिया। रैली में प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ-साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के उद्बोधन में भी किसानों, इन्सेफ्लाइटिस से पीड़ित मासूमों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास से सम्बन्धित किसी भी बात का जिक्र न होना उनके विकास विरोधी चरित्र और किसानों के प्रति संवेदनहीनता को प्रदर्शित करता है। योगी जी ने जिला प्रशासन को आगाह किया कि विकास प्राधिकरण के नाम पर गरीब किसानों की जमीनों को जबरन हड़पने का भारी विरोध होगा। यह आश्चर्यजनक है कि महानगर के अन्दर मानबेला और उसके आस-पास के क्षेत्र के किसानों की जमीन जबरन अधिग्रहीत करके रुपया 6 लाख से 8 लाख प्रति एकड़, जंगल तिनकोनिया और खोराबार में रुपया 11 लाख से 12 लाख प्रति एकड़ का भुगतान करके औने-पौने दाम पर किसानों की जमीनों को हड़पा जा रहा है जबकि निजी

कालोनाइजर्स इन क्षेत्रों में किसानों की जमीन रुपया 2 से 2.5 करोड़ प्रति एकड़ के हिसाब से बेच रहे हैं। जी.डी.ए. प्राइवेट कालोनाइजर्स के साथ मिलकर यहां के किसानों के पेट पर लात मारने का कार्य कर रहा है जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

गन्ना किसानों के सम्बन्ध में बोलते हुए योगी जी ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का मुख्य कैश क्रॉप गन्ना की खेती थी। आज प्रदेश सरकार की उपेक्षा और भ्रष्ट रवैये के कारण गन्ना किसान तबाह है। चीनी मिलें एक-एक करके बन्द हो रही हैं या उन्हें औने-पौने दाम पर बेचा जा रहा है। अभी भी गन्ना किसानों का सैकड़ों करोड़ रुपया बाकी है जिसका भुगतान होना है। यह आश्चर्यजनक है कि पिछले वर्ष गन्ना मूल्य रुपया 290 प्रति कुन्टल था। इस वर्ष प्रदेश सरकार ने चीनी मिलों के साथ मिलकर इस दाम को घटाकर रुपया 260 प्रति कुन्टल कर दिया। जबकि हरियाणा सरकार ने रुपया 310 प्रति कुन्टल किसानों को भुगतान कर रही है। प्रदेश सरकार अपने कृत्यों से भ्रष्ट है। उसका आचरण किसान विरोधी है। जिला प्रशासन को किसानों की ओर से ज्ञापन सौंपते हुए मांग किया गया कि -

1. किसानों की जमीनों का अधिग्रहण करने के पहले प्रभावित किसानों से बातचीत कर उनकी सहमति से मुआवजा रेट तय किये जायं एवं मुआवजा भुगतान होने के उपरान्त ही भूमि का अधिग्रहण किया जाय।

2. गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जिन क्षेत्रों के किसानों की भूमि अधिग्रहण होनी हो उन गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक शौचालय सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं पहले उपलब्ध कराईं जायं।

3. जिन क्षेत्रों के किसानों की भूमि अधिग्रहण करने की कार्यवाही हो उन क्षेत्रों में पहले से मौजूद आवास, धर्मस्थल, शिक्षण संस्थान, गोशाला, भैंस पालन केन्द्र, मुर्गी पालन केन्द्र, घुड़साल, बाग, सहन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि की भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही से मुक्त रखा जाय।

4. गन्ना किसानों का चीनी मिलों के पास पिछले बकाये का भुगतान अविलम्ब कराया जाय एवं भविष्य में गन्ना किसानों का भुगतान नियमित होता रहे, यह सुनिश्चित किया जाय।

# प्रदेश सरकार किसान विरोधी : योगी

गोरखपुर (एसएनबी)। गोरखपुर विकास प्राधिकरण से पीड़ित किसानों तथा गन्ना किसानों की समस्या का समाधान अविलम्ब हो। विकास के नाम पर चल रही लूटखसोट का शिकार अगर किसानों को बनाया गया तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जायेगा।

सदर सांसद योगी आदित्यनाथ ने मानबेला, मिर्जापुर, झुंगिया, जंगल तिनकोनिया, खोराबार आदि क्षेत्र के गोरखपुर विकास प्राधिकरण से पीड़ित किसानों द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष आयोजित धरना कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसान विरोधी है। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी को मानबेला में समाजवादी पार्टी की रैली में मौजूद प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर विकास प्राधिकरण से पीड़ित किसानों की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में न तो कुछ कहा गया और न ही किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान से सम्बन्धित वक्तव्य ही दिया। रैली में प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ-साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के उद्बोधन में भी किसानों, इन्सेफेलाइटिस से पीड़ित मासूमों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास से सम्बन्धित किसी भी बात का जिक्र नहीं था। योगी ने कहा कि महानगर के अन्दर मानबेला और उसके आस-पास के क्षेत्र के किसानों की जमीन 6 लाख से 8 लाख प्रति एकड़, जंगल तिनकोनिया और खोराबार में 11 लाख से 12 लाख प्रति एकड़ का भुगतान करके औने-पौने दाम पर हड़पा जा रहा है जबकि निजी कालोनाइजर्स इन क्षेत्रों में किसानों की जमीन 2 से 2.5 करोड़ प्रति एकड़ के हिसाब से बेच रहे हैं। जीडीए प्राइवेट कालोनाइजर्स के साथ मिलकर यहां के किसानों के पेट पर लात मारने का कार्य कर रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का मुख्य कैश क्रॉप गन्ना की खेती थी। पिछले वर्ष गन्ना मूल्य 290 रुपए प्रति कुन्टल था। इस वर्ष प्रदेश सरकार ने चीनी मिलों के साथ मिलकर इस दाम को घटाकर रुपया 260 प्रति कुन्टल कर दिया। जिला प्रशासन को किसानों की ओर से ज्ञापन सौंपते हुए मांग किया कि किसानों की जमीनों का अधिग्रहण करने के पहले प्रभावित किसानों से बातचीत कर उनकी सहमति से मुआवजा रेट तय किये जाय। मुआवजा भुगतान होने के उपरान्त ही भूमि का अधिग्रहण किया जाय। गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जिन क्षेत्रों के किसानों की भूमि अधिग्रहण होनी हो उन गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक शौचालय सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं पहले उपलब्ध कराई जाय। धरना कार्यक्रम में हरिद्वार पाण्डेय, बेचन निषाद, राम प्रताप मौर्या, किसान नेता बरकत अली, हरिशंकर सिंह, राजेश शर्मा प्रधान, अमृतलाल भारती, हियुवा के प्रदेश महामंत्री रामलक्ष्मण, प्रदेश कार्यालय प्रभारी ई पी के. मल्ल, अमित पाण्डेय, धनंजय तिवारी, मो. जफरूद्दीन अंसारी, राम उजागिर शर्मा, सुहेल, अलीमुन निषाद, चन्द्रभान, अमरनाथ, पार्षद वीर सिंह सोनकर, पार्षद धर्मदेव चौहान, पार्षद रवीन्द्र प्रताप सिंह्, पार्षद मंगलाल आदि उपस्थित रहे।

किसान मजदूर संघर्ष समिति के धरने को जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में सम्बोधित करते सांसद योगी आदित्य नाथ।

■ गोरखपुर विकास प्राधिकरण से पीड़ित किसानों ने डीएम कार्यालय के समक्ष दिया धरना